



## यूपी उपचुनाव की तारीख बदली

● यूपी, पंजाब और केरल की 14 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख बदली, त्योहारों की वजह से लिया गया फैसला



नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, RLD और अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के अनुरोध पर और कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए चुनाव आयोग ने तीन राज्यों केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर से 20 नवंबर तक पुनर्निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल की 14 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। इन सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक, विभिन्न त्योहारों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर से 20

नवंबर को पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। इस वजह से लिया गया फैसला बताया गया कि कांग्रेस, भाजपा, बसपा, RLD और अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के अनुरोध पर और कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए चुनाव आयोग ने तीन राज्यों केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर से 20 नवंबर तक पुनर्निर्धारित किया है। जानकारी के मुताबिक, प्रकाश पर्व और तुलसी विवाह जैसे पर्वों

## झारखंड में अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार जनता की पुकार एनडीए सरकार



● मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, हेमंत का जिफ्र नही: जेएमएएम, राजद-कांग्रेस को परिवारवादी कहा, पर भाजपा ने 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा  
● भ्रष्टाचार, पेपरलीक से लेकर परिवारवाद और झूठे वादों तक, झारखंड में सोरेन सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी

शंघी, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री ने कहा कि JMM-कांग्रेस-RJD ने तुष्टिकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना-बाना तोड़ने पर आमादा हैं, ये तीनों दल घुसपैठिया

समर्थक हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प रहे हैं।

मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद को जमकर घेरा। उन्होंने भ्रष्टाचार, पेपरलीक से लेकर परिवारवाद और झूठे वादों तक, लगभग हर मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार को खरी-खोटी सुनाई। झारखंड में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी अलायंस की सरकार को उखाड़कर कमल खिलाने को आतुर है झारखंड की जनता! आपने कुछ महीने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार भाजपा-एनडीए सरकार बनाई। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, हम सभी को मिलकर यहां

भाजपा-एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गूंज है, शरोटी-बेटी-माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा-एनडीए की सरकार। उन्होंने कहा कि इस समय छठ का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वालों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड में ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं, जब पूरा देश शकिसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है यानी आने वाले 25 वर्ष देश और झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

## सपा महाराष्ट्र में वापस ले सकती है कुछ घोषित प्रत्याशी

लखनऊ, (एजेंसी)। सपा महाराष्ट्र का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ना चाहती है। पार्टी ने अपने प्रत्याशी जरूर उतार दिए हैं लेकिन समझौता होने पर वह नाम वापस ले सकती है। यूपी के उपचुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा में गठबंधन नहीं हो सका। इधर महाराष्ट्र में भी सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। बावजूद इसके पार्टी अभी गठबंधन हो जाने की आशा में है। महाराष्ट्र के चुनाव में सपा को अब भी गठबंधन से जवाब का इंजाए है। जिन 10 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि 4 नवंबर है। अगर बात बनी तो सपा नेतृत्व कुछ प्रत्याशियों को मैदान से हटाने पर विचार कर सकती है। सपा ने महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीती थीं। इस बार इन दोनों समेत कुल 10 सीटों पर अभी सपा प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सपा के प्रत्याशी उतारने पर इन सीटों पर मुस्लिम के साथ वहां रह रहे यूपी के लोगों के मत बंट सकते हैं। इससे कम मार्जिन से जीत-हार तय होने पर गठबंधन के प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। पार्टी के महाराष्ट्र इकाई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, प्रयास यही है कि अगर गठबंधन के तहत उन्हें 3-4 सीटें देने पर भी सहमति बनी तो शेष सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी वापस ले सकेगी। अन्यथा की स्थिति में सपा इन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी।

## यूपी कैबिनेट बैठक 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

● अब पांच के बजाए 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला

लखनऊ, (एजेंसी)। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया। शिक्षक अब पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ तीन साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पैरावेट के लिए डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए भी नीति को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति को मंजूरी दे दी



डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स हेतु नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी। आबकारी विभाग शीरा नीति-उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी, 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के शीरा 19 हेतु शीरा रिजर्वेशन को मंजूरी, 19 नवंबर केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति, बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा पशुपालन विभाग प्रदेश में पशु मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति को मंजूरी दे दी

## नदी में बिरवरीं लाशों ही लाशों

● अल्मोड़ा में दिल दहला देने वाला हादसा

अल्मोड़ा, (एजेंसी)। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मार्चुला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। घटनास्थल पर चीख पुकार मची है। जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मार्चुला इलाके के पास सोमवार को यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई। बस में 55 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसएसपी अल्मोड़ा मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। घटनास्थल पर बचाव



नदी में लगा लाशों का ढेर... दर्दनाक तस्वीरें

अभियान चल रहा है। हादसे में 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। बस नैनीताल के किनाथ से रामनगर जा रही थी। जैसे ही बस मार्चुला के पास पहुंची तो सारड बैंड के पास नदी में गिर गई। बस के नदी में गिरते ही चीख-पुकार मच गई। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बस से छिटककर नीचे गिर गए। घायल लोगों ने ही जानकारी दूसरों तक पहुंचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाया। घायलों को अस्पताल ले जाने का काम किया गया। बस सवार 36 यात्रियों की मौत हो गई। नदी में लाशों का ढेर लग गया। चारों ओर भयावह मंजर था। मुश्किल

से बस के अंदर फंसे शवों को निकाला गया। शुरुआती जानकारी मिली है कि यूजर्स कम्पनी की बस है। बस 42 सीटर है। लेकिन 55 से अधिक यात्री बस में सवार थे। सड़क हादसे पर दुख जताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद अल्मोड़ा के मार्चुला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया है। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं SDRF की टीमों घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु तेजी से कार्य कर रही हैं।

## आर्थिक स्तर पर विफल मोदी देश को बरगला रहे हैं: स्वर्गे

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए आज कहा कि वह आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करने में माहिर हैं, देश की अर्थव्यवस्था हर स्तर पर गिरी है, लेकिन इस विफलता को लेकर वह देश की जनता को भ्रमा रहे हैं। श्री खरगे ने कहा, "श्री नरेन्द्र मोदी जी नकली आख्याना वास्तविक कल्याण का विकल्प नहीं हो सकते। आम नागरिकों का पैसा लूटकर जो आर्थिक उथल-पुथल आपने पैदा की है, उससे त्योंही खुशी कम हुई, उच्च मुद्रास्फीति से असमानता बढ़ी, कम निवेश हुआ और स्थिरता से जुड़ा रही अर्थव्यवस्था का निरुत्साहित रही। आपकी सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग पर कमरतोड़ महंगाई थोपकर और बिना सोचे-समझे करधान के माध्यम से उनकी बचत को खत्म करके उन्हें बड़ा झटका दे रही है।" उन्होंने कहा, "आपकी सरकार के जनविरोधी निर्विवाद पांच तथ्य हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। खाद्य मुद्रास्फीति 9.2 प्रतिशत पर है। सब्जियों की मुद्रास्फीति अगस्त में 10.7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 14 महीने के उच्चतम 36 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह सच है कि एफएमसीजी सेक्टर की मांग में भारी गिरावट देखी गई है, बिक्री में वृद्धि एक साल में 10.1 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 2.8 प्रतिशत रह गई है। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट यह बताती है। एफएमसीजी कंपनियों ने मार्जिन में गिरावट की सूचना दी है और कहा है कि अगर कच्चे माल की लागत कंपनियों के लिए असहनीय हो गई, तो इससे कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।" कांग्रेस अध्यक्ष ने घरेलू बचत को लेकर भी सरकार पर हमला किया और कहा, "घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर आ गई है।"



## बेअंत हत्याकांड: बब्बर खालसा सदस्य राजोआना को नहीं मिली राहत

● बेअंत हत्याकांड के दोषी की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- फैसला लें वरना हम विचार करेंगे



नई दिल्ली, (एजेंसी)। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि अगर वे बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर विचार नहीं करते हैं तो हम करेंगे। बेअंत सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, साल 1995 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में बलवंत सिंह राजोआना को दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। याचिका में कहा गया है कि उसकी दया याचिका पर फैसला लेने में हुई

जल्दी हो दया याचिका का निपटारा, जिससे पीड़ित को न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट

बहुत देरी के कारण उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल देना चाहिए। 25 सितंबर को शीर्ष अदालत ने राजोआना की याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन से जवाब मांगा था। राष्ट्रपति के पास लंबित है याचिका केंद्र की ओर से पेश हुए सिलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति भवन में लंबित है, जिसके बाद पीठ ने उनसे कहा, शकिसी भी तरह से फैसला करें या हम

इस पर (राजोआना की याचिका) विचार करें। दया याचिका पर फैसला होने तक राजोआना की रिहाई की मांग करते हुए राजोआना के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रहेतगी ने कहा कि राजोआना 29 साल से लगातार हिरासत में है। रोहतगी ने कहा कि शउनकी दया याचिका पिछले 12 साल से राष्ट्रपति भवन में लंबित है। कृपया उन्हें छह या तीन महीने के लिए रिहा कर दें। कम से कम उन्हें यह देखने दें कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है।





